टाइम्स ऑफ़ पीडिया

TIMES OF PEDIA

ٹائمس آف پیڈیا

NEW DELHI Page 12 Price ₹ 3.00

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इंसाफ़ की डगर पर

www.timesofpedia.com

WEEKLY HINDI ENGLISH URDU

WED 24 FEB - TUE 01 MAR 2016 VOL. 4 Issue 17 RNI No. DELMUL/2012/47011 P.Reg. No. DL(S) - 01/3431/2013 - 15

संपादकीय

आम बजट , आम आदमी के लिए या ...

आम बजट की रकम हर साल 10 से 20 प्रतिशत बढ़ाई जाती है मगर गरीबी की रेखा और लम्बी हुई जाती है और अमीरी की भी, यानि देश के छोटे शहरों का भी बाइंग रेट बढ़ा है जबकि किसानो और गरीबों की आत्महत्याओं का भी अनुपात लगातार बढ़ ही रहा है, अवाम को यह समझ नहीं आता की आम बजट है किसके लिए हालाँकि देश के हर वर्ग की निगाह इसपर टिकी होती है मगर इसके पेश होने के बाद हफ्ता दस दिन टीवी चौनल्स पर विशेषज्ञों की तीखी बहस और विपक्ष के साथ सत्ता धारी नेताओं की नोक झोंक के बाद समाज से इस की चर्चा खत्म होजाती है इसके बाद क्या अच्छा और क्या बुरा बजट।

लास्ट संडे प्रधानमंत्री मोदी आल इंडिया रेडियो पर मन की बात में देश के बच्चों को परीक्षा में सफलता की टिप्स दे रहे थे और कह रहे थे मुझे भी देश की सवा करोड़ जनता के सामने अपनी परीक्षा देनी है यानी आम बजट पेश होना है। अब अपनी परीक्षा में वो सफल हुए या असफल यह कौन बताएगा चलिए आप ही बता दें मोदी साहब क्योंकि अभी तो आप ही परीक्षक हैं और परीक्षार्थी भी आप, वैसे आप अपने मन की बात की जगह जनता की मन की बात सुनते तो बात ही कुछ और होती, मगर आपको तो .....

अच्छा क्या हमको भी खामोश रहना चाहिए क्योंकि देश में देशभक्ति और देशद्रोह के सर्टिफिकेट्स वितरण का माहौल है वैसे हमको खामोश नहीं रहना चाहिए क्योंकि सच्चाई देश के सामने लाना हमारा कर्तवय है, हम चाल बाजी के लिए नहीं इन्साफ जिंदा करने के लिए पैदा हुए हैं, रहा मौत और जिंदगी यह रब के ही हाथ है किसी इंसान के नहीं.. मगर इंसान हैं कोई गुनाह भी हो सकता है। दुनिया में होना वही है जो इसके बनाने वाले ने लिख दिया है मगर फिर भी न जाने क्यों नहीं समझते लोग।

किसान आंदोलन और जाट आरक्षण से बोखलाई केंद्र सरकार पर इस बात का दबाव तो रहा होगा की आग को ठंडा करने के लिए बजट 2016 के पिटारे में जरूर कोई सांप रखा जाए चाहे मारा हुआ ही क्यों न हो चुनाचे इस बजट में किसानो की आमदनी 2022 तक दुगनी कर देने का सुहाना सपना रखा गया मगर यह तो पता करना जरूरी है की किसान की आमदनी है कितनी तभी तो दुगनी का अंदाजा होगा ,17 राज्यों में कराये गए राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के अनुसार मध्यस्थ किसान की सालाना आमदनी 20,000 बताई गयी है। यानी 1666 रूपये प्रतिमाह इसका दुगना 3332 हुआ क्या यह सपना इतना बड़ा है की इसका इंतजार 2022 तक भारत के किसान को करना चाहिए? शायद वित्त मंत्री इस बात को रखने से चूक गए की यह आमदनी 2017 तक ही दुगनी करदी जायेगी, मगर ऐसा शायद इसलिए न कहा गया हो की लोग इसको जादू की छड़ी न कहने लगें आखिर मोदी कैबिनेट के स्मार्ट मंत्री ठहरे जेटली जी . खैर जो भी हो फिलहाल बजट में गुड फील होने या अच्छे दिन वाली कोई बात देश के बड़े आर्थिक विश्लेषकों को नजर नहीं आई भले ही चापलूस टीवी चैनल्स बजट के कितने ही कसीदे पढ़ते रहे हों हालाँकि इस बजट को आम आदमी की बुनयादी जरूरतों को सामने रखकर बनाये जाने की बात भी कही गयी है लकिन इसका अंदाजा अगले 6 महीनो में ही सरकार की किर्यान्वियन नीति के साथ हो पायेगा जिस मुस्तैदी के साथ हमारा मीडिया बजट को प्रकाशित व प्रसारित करने में अपनी कर्मठता दिखाता है यदि उसी ईमानदारी के साथ इसके किर्यान्वियन पर भी अपनी भूमिका निभाये तो शायद देश की आम जनता का भला हो सके वर्ना सरकार पर पूँजीवाद, सामंतवाद और मनुवाद का पक्षधर होने का इलजाम तो लग ही रहा है।

Editor's Desk

प्रधानमंत्री से वैचारिक मतभेद, हमें आजादी चाहिएः कन्हैंया

नई दिल्लीः देशद्रोह के फर्जी आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गयी और उनको तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। कन्हैया कुमार ने अपनी रिहाई के लिए आज दोपहर दिल्ली की एक अदालत में 10 ,000 रूपये की जमानत राशि जमा की, खबर सुनकर जेएनयू से उनके गांव तक में खुशी का माहौल है। कन्हैया की रिहाई के बाद आज जेएनयू में एक स्वागत मार्च निकाला गया। साथ ही एक सभा का आयोजन भी किया गया जिसमें जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के बीच खुलकर अपनी बात रखते हुए केंद्र का संगीन आरोप लगाया गया क्या उस विचारधारा को देश की बाकी राजनितिक पार्टियां समर्थन करती हैं? अगर हाँ तो क्या इस आंदोलन में जुड़कर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे?अगर नहीं तो यह मान लिया जाए की दूसरी पार्टियां भी आरएसएस विचार धरा से तो सहमत नहीं किन्तु लेफ्ट के नजरये को भी देश में पनपता नहीं

जिसके बाद उनकी जेल से शाम को रिहाई हो पाई।याद रहे हाईकोर्ट ने कन्हैया को कुछ शर्तों पर छह महीने के लिए अंतरिम जमानत दी। इस बीच कन्हैया को जेएनयू लेजाते वक्त तक पुलिस की तीन कार एस्कॉर्ट कर रही थीं। कन्हैया की रिहाई चुपचाप तरीके से की गई और उनकी जमानत के बाद किसी भी दुर्घटना के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे हालांकि उनकी सुरक्षा को लेकर अभी भी खतरा बताया जा रहा है याद रहे कन्हैया को कोर्ट में पेशी के दौरान हमला हो गया था जिससे दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में आगई थी। कन्हैया पर देशविरोधी नारे लगाने का आरोप में दिल्ली पुलिस कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। कन्हैया की जमानत की सरकार और भाजपा एवं उसकी छात्र इकाई एबीवीपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी किसी के प्रति कोई नफरत नहीं और देश की न्याायिक व्यवस्था पर भरोसा है। उन्होंने कहा हम एबीवीपी को विपक्ष की तरह देखते हैं और पीएम से हमारे भारी वैचारिक मतभेद हैं।जेएनयू पर हमले को नियोजित बताते हुए कन्हैया ने कहा हमें देश से नहीं, देश में आजादी चाहिए, भुखमरी, अत्याहचार से आजादी चाहिए हम भारत में आजादी मांग रहे हैं।हमारा किसान आत्म हत्याएं कर रहा है, सीमा पर जवान शहीद होरहे हैं उन सबको हमारा सलाम।

ऐसे में एक सवाल यह पैदा होता है की कन्हैया जिस विचारधारा के चलते गिरफ्तार किये गए और उनपर देश द्रोह देखना चाहते और कन्हैया जैसे मामूली लड़के को इस क्रांति के हीरो के रूप में भी, हमको लगता है देश में आंदोलनों का मौसम आगया है अन्ना आंदोलन, पटेल आंदोलन, किसान आंदोलन, जाट आंदोलन और कन्हैया आंदोलन, हालाँकि जो लोग बदलाव के इन आंदोलनों को समझ गए वो 11 महीने पुरानी पार्टी के नाम पर ही देश के दिल यानी दिल्ली पर भारी बहुमत से सत्ता में आगये यदि आज के कन्हैया आंदोलन से जुड़कर कुछ चवसपजपबंस लाभ उठाना चाहें तो शायद यह उन पार्टिओं के लिए सुनहरी मौका होसकता है जो संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं भी और देश में अमन और शांति तथा विकास के लिए भी।

टॉप ब्यूरो

Ishrat case: GK Pillai's Adani link

New Delhi: Former home secretary GK Pillai did not include any note of dissent in the second affidavit on Ishrat Jahan from which he had distanced himself last week, a document accessed by The Telegraph reveals.Pillai has also confirmed to this newspaper that he is now an independent director with Adani Ports, a company chaired by Gautam Adani whose one- time proximity with Narendra Modi was cited by the Opposition to criticise the PM.Pillai had said Chidambaram had changed the affidavit " bypassing" bureaucrats. BJP has seized the opportunity to seek a judicial inquiry into the case and the alleged role of Chidambaram.The Telegraph today accessed the file

noting dated Sept. 24, 2009, where Chidambaram, the then home minister, had written: "As amended (2nd affidavit) please show clear copy…." The very same day, Pillai had written and signed: "Clear copy shown to the home minister. Send it for filing." "Why did Pillai not write a note of dissent on the file if he had any objections to it then?" asked a ex-Union home secretary who requested anonymity.Asked the same question by this paper, Pillai said: " He (Chidambaram) was my political boss and that's why I did not think of putting my note of dissent on the file." Pillai retired as home secretary in June 2011. GK Pillai is now shown as on the board of Adani Ports as an independent and non- executive director.

Agency

Editor/Owner/Printer/Publisher: Ali Aadil Khan, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar, Okhla, ND - 25. **Printed at :** Shobi Offset Press, 2818, Gali Gadhiaiya, Kuchachalan, Daryaganj, ND. - 2

समाचार पत्रों के आईने से

खली का ऐलान, खून का बदला खून से लूंगा, अब कोई ताकत लड़ने से नहीं रोक सकती

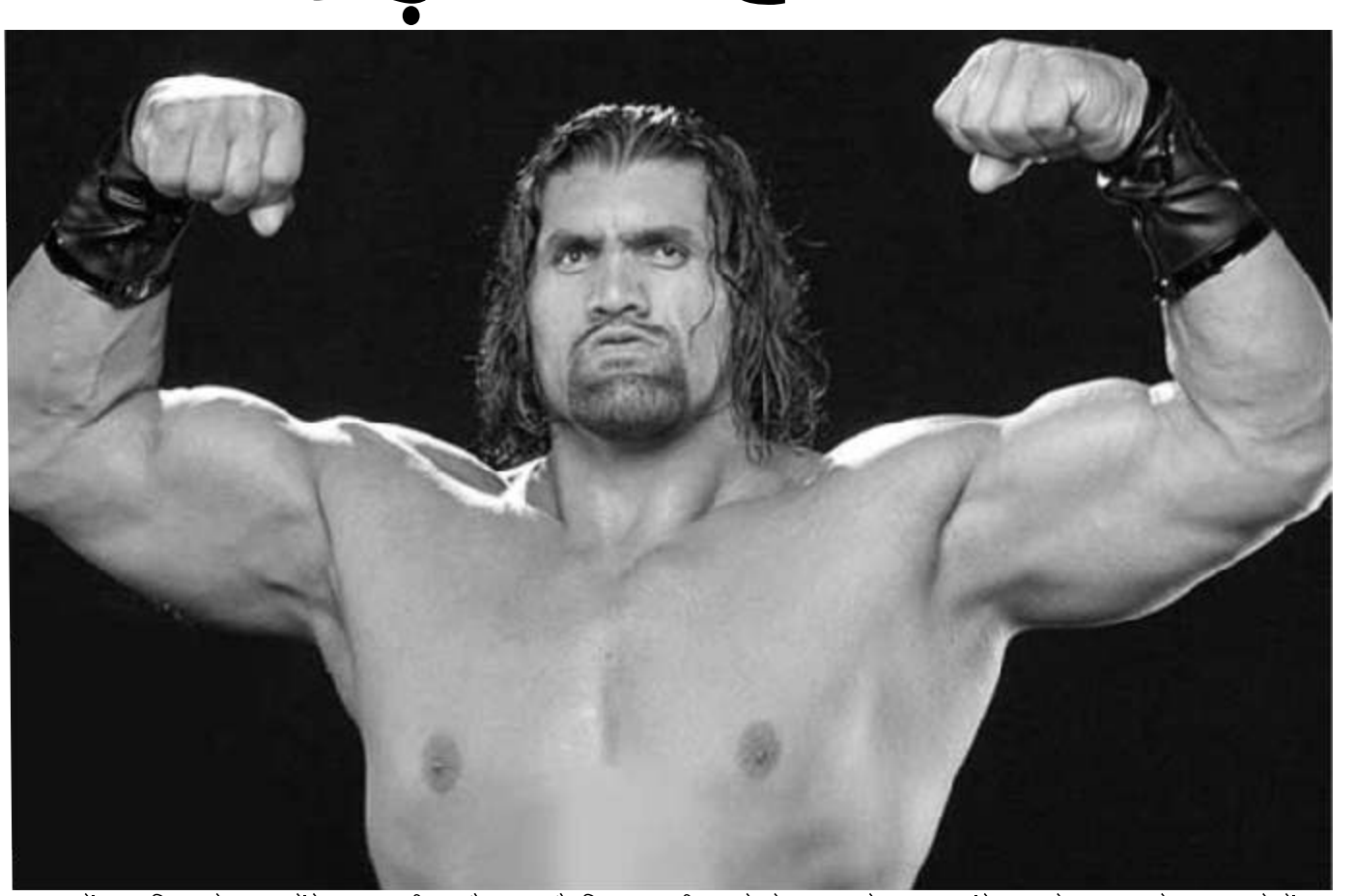

देहरादूनः उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुधवार 24 फरवरी को रेसलिंग में घायल हुए खली ने कहा है कि वो अब कनाडा के तीनों पहलवानों को उसी तरीके से रिंग में मारकर बदला लेंगे। ग्रेट खली ने कहा कि मुझे धोखे से मारा गया और इसका बदला में कनाडा के तीनों पहलवानों को मार कर लूंगा। यही नहीं खली ने कहा की खून का बदला खून से ही होगा।

सिर पर 7 टांके, गंभीर चोट, उस पर भी डॉक्टरों का कहना कि खली के लिए फाइट करना मुश्किल है, पर फिर भी 24 तारीख को हल्द्वानी में हुए अपमान का बदला लेने के लिए खली किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

खली की मानें तो वो रिंग में खून ही खून बहाना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, खून का बदला खून से ही लेने को आतुर खली बेहद क्रोध में दिख रहे हैं।

खली पर लोहे की जिस कुर्सी से वार किया गया था, उसी तरह की लोहे की कुर्सी से अंडर टेकर को धूल चटा चुके खली कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको लड़ने से नहीं रोक सकती। चाहे सिर पर चोट हो या पूरा जिस्म छलनी छलनी हो जाए, वो हल्द्वानी में हुई अपनी बेइज्ज़ती का बदला कनाडा के पहलवानों का सिर फोड़कर लेंगे। साथ ही खली ये कहने से भी नहीं चूके कि मैंने अपना डेथ वारंट तो पहले ही साइन कर दिया है। गौरतलब है कि 28 तारीख को देहरादून के स्टेडियम में रेसलर्स दोबारा एक–दूसरे से फाइट करेंगे और अपनी ताकत का ऐहसास करवाएंगे। सबसे ज्यादा जो फाइट लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी वो खली की ही होगी।

NDTV

जो आज अफजल गुरू का समर्थन कर रहे हैं मारे जा चुके होतेः जज एसएन ढींगरा

नई दिल्लीः जेएनयू में अफजल गुरु का समर्थन करने के मामले में उनका साथ देने के लिए विपक्ष के नेताओं पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा ने कहा कि अगर यह हमला कामयाब हो गया होता इनमें से कई मारे गए होते।

2002 में संसद पर हुए हमले के मामले को देखने वाले जज ढींगरा ने जेएनयू में अफजल समर्थकों के साथ मंच साझा करने पर नेताओं की आचोलना की है। उन्होंने कहा कि जो लोग अफजल का समर्थन कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर उस ग्रुप का हमला जिस ग्रुप में अफजल था, कामयाब हो जाता तो आज जबकि सांसद उसकी तरफदारी कर रहे हैं उनमें से 40–50 मारे जा चुके होते, तब बात ही अलग होती। चूंकि इस हमले में केवल 15 आम आदमी ही मारे गए थे, इसलिए हम अफजल का शहीदी दिवस मनाना चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि जेएनयू में कुछ छात्रों द्वारा अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की सालगिरह मनाने के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। इस मुद्दे पर संसद में काफी बहस हुई है। जेएनयू स्टूडेंट्स द्वारा अफजल गुरु की फांसी को ज्यूडिशियल किलिंग कहे जाने पर भी जस्टिस ढींगरा ने आपत्ति जताई। न्यायपालिका को यह हक ऐसे आदमी को मारने के लिए दिया गया, जो समाज के लिए खतरा बन गया हो। आईपीसी में इस संबंध में प्रावधान है और यह हक देता है और जरूरी बनाता है कि अगर कोई शख्स खतरा बन गया है, तो उसे यह सजा दी जाए। अगर यह जूडिशियल किलिंग है तो जो सजा दी जाती है उसे क्या जीवन बरबाद करने वाली कहा जाएगा। छात्रों पर देशद्रोह का आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह देश का कानून है, लेकिन पुराना हो चुका है।

अगर आप कानून के हिसाब से देखें तो एक शब्द भी काफी है। अगर शब्दों के साथ किसी एक्शन को जोड़ दिया जाए तो न जेएनयू का छात्र, न हार्दिक और न ही जय प्रकाश नारायण, कोई भी दोषी नहीं है। जेपी ने भी ऐसा ही कहा था और देशद्रोह का आरोप लगा। हम कहते हैं कि कानून पुराना है। हमारे अधिकतर कानून पुराने हैं और ब्रिटिश के जमाने से हैं या बाहर से लिए गए हैं।

NDTV

NOTICE:
Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to in accuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

स्मृति विवाद के बाद राज्यसभा में बिलों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ी

नई दिल्लीः जेएनयू विवाद और हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला के खुदकुशी मामले में सरकार और विपक्ष के बीच शुक्रवार को हुई तीखी तकरार के बाद राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान विधेयकों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

यह विवाद तब बढ़ा जब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वह पर्चा पढ़ना शुरू किया जो कथित तौर पर जेएनयू परिसर में वितरित किया गया था, इसमें कथित तौर पर मां दुर्गा के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे जेएनयू छात्रों के एक वर्ग की ओछी मानसिकता का पता चलता है। राज्यसभा में इस बहस के दौरान उस समय व्यजवधान पैदा हुआ जब समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर मंत्री से बयान को वापस लेने और माफी मांगने की मांग कही। हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। गौरतलब है कि राज्यसभा में सरकार अल्पंमत में है।

राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने कहा, पहले भी लोगों ने ईशानिंदा वाले बयान जारी किए है, लेकिन कभी भी सदन के पटल पर ऐसे बयानों को कोट नहीं किया गया या दोहराया नहीं गया। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा, इसे जानबूझकर कोट किया गया। बीजेपी पूरी बहस का ध्रुवीकरण करना चाहती है। आखिर इस पूरे मामले में मां दुर्गा को लाने की जरूरत क्या थी। स्मृति को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार इस बात पर अडिग है कि स्मृति ने कुछ गलत नहीं किया। एक मंत्री ने कहा, श्स्मृति ने ईशनिंदा जैसी कोई बात नहीं की। वे महज यह तर्क रखना चाहती थीं कि इससे पहले भी जेएनयू से आपत्तिजनक सामग्री आती रही है।श हालांकि शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर्स के बिल के लिए तय है, लेकिन विपक्ष जेएनयू विवाद पर बहस को जारी रखने के पूरे मूड में है। संसद सत्र शुरू होने से पहले सरकार और विपक्ष के बीच किसी भी बिल को पेश करने से प्रमुख मुद्दों पर बहस कराए जाने को लेकर जो सहमति बनी थी वह अब बिखरकर रह गई है।

NDTV

Grave doubts about Afzals involvement in Parl attack Chidambaram

Former Union minister P Chidambaram has said there were “grave doubts” about the involvement of Afzal Guru in the 2001 Parliament attack and that the case was “perhaps not correctly decided”. Chidambaram was Union home minister when Guru's mercy plea was rejected by the previous UPA government in 2011. Guru was hanged two years later.“There were grave doubts about his involvement (in the conspiracy behind the attack on Parliament) and even if he was involved, there were grave doubts about the extent of his involvement. He could have been imprisoned for life without parole for (the) rest of his natural life,” Chidambaram was quoted as saying by The Economic Times.

Chidambaram was responding to questions from ET on whether the courts had reached the correct conclusions in the Afzal case and also whether execution was the appropriate penalty. An event commemorating Guru's hanging turned into a controversy after police charged six students with sedition for attending the function at the Jawaharlal Nehru University (JNU) earlier this month. Kashmiri separatists have also sought to use his execution to rally support.“I think it is possible to hold an honest opinion that the Afzal Guru case was perhaps not correctly decided,” said the senior Congress leader who was the home minister from 2008 to 2012.

To a question that he was also in the government that executed Guru, Chidambaram said he was “not the home minister then”. “I can't say what I would have done. It is only when you sitting on that seat you take that decision.”Chidambaram said though the government of the time could not have held the court decision wrong, “an independent person can hold an opinion that the case was not decided correctly”.He said it was wrong to brand anyone with the same view as “anti-nation” and added the sedition charges against JNU students were “outrageous”. “Free speech is not seditious speech. Is your speech a spark in the powder keg (inciting violence) only then it amounts to sedition,” he said. Chidambaram also said the anti-national slogans allegedly chanted on the JNU campus did not amount to sedition. “It is an age where students have the right to be wrong…And the university is a place where you don't always need to be profound, you can be ridiculous also,” he added.

CROSSINGS Republik™

READY 2 MOVE IN FLATS

in

CROSSINGS REPUBLIC-NH24

India's First Global city

- 9 KM from Noida City Centre,
- 15 km from Kalindikunj
- 12 km Anand Vihar
- Just Adjacent to Noida Extension
- Approx 200 families already shifted
- Club/Swimming pool
- Power backup/market complex
- Huge jogging track
- Magnificent golf course in order
- 80% open area
- A Unique complex in whole of NCR

SIZE : 2 bed room 1270 sq ft. • 3 bed room 1725 ft.
nicely built-up flats vitrified tiles, wooden flooring in master bedroom, complete tiling and sanitary fittings in bathrooms, kitchen, large dinning/drawings/4 balconies
PRICE: 2 bed room 28-lacs onwards • 3 bed room 38 lacs onwards
all inclusive (Covered car parking, club membership, power back up 1 KV, EDC/IFFC/IFMC etc.)

Contact:

CITY ESTATE

A real estate service provider and Marketing Channel Partner of many reputed builders in NCR

Branch Offices: • 301, JOP Plaza, Sector 18, Noida • Shop No 22, Gallaria Complex, Crossings Republic.
Email: city_realestate@yahoo.co.in

मानव भविष्य बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने आसपास पेड़ लगाएं और गंदगी न होने दें।

भारत में जाति व्यवस्था पर आरएसएस का रूख

रोहित वैमूला की आत्महत्या ने देश को स्तब्ध कर दिया है और जातिगत भेदभाव व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर देशभर में बहस चल रही है। रोहित, प्रतिष्ठित हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी अध्यक्षता थे। वे दलित थे और विश्वविद्यालय में सक्रिय अम्बेडकर स्टूडेंटस एसोसिएशन (एएसए) से जुड़े हुए थे। विज्ञान उन्हें बहुत आकर्षित करता था और वे अम्बेडकर के लेखन और उनकी सोच के लेंस के सहारे सत्य की खोज में रत थे। वे जाति की समस्या से बहुत व्यथित थे और उसके हल के लिए कुछ करना चाहते थे। एएसए ने याकूब मैमन को फांसी दिए जाने के खिलाफ एक बैठक का आयोजन किया क्योंकि वह सिद्धांततः मृत्युदंड के खिलाफ था। इस बैठक में आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी के सदस्यों ने हंगामा किया। इसके पहले, रोहित ने दिल्ली विश्वविद्यालय में ''मुजफ्फरनगर बाकी है'' फिल्म के प्रदर्शन को जबरदस्ती रोके जाने का विरोध किया था। ऐसा आरोप है कि रोहित ने सन् 2015 में एबीव्हीपी के एक नेता पर हमला किया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं। बाद में यह पता चला कि एबीव्हीपी नेता एपेंडिसाईटिस के आपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे ना कि चोट के इलाज के लिए। इसके बाद भी, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने रोहित को निलंबित कर दिया और उनकी शिष्यवृत्ति बंद कर दी गई। विश्वविद्यालय की इस प्रतिशोधात्मक कार्यवाही के चलते रोहित को अपने घरवालों को पैसा भेजना बंद करना पड़ा, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी।

रोहित और एएसए के अन्य छात्रों को उनकी विचारधारा और राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के लिए ''राष्ट्रविरोधी, अतिवादी और जातिवादी'' बताया गया। ये आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार दोनों ने लगाए। उनकी मां ने हाल में इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया कि अन्य राजनेताओं के विपरीत, प्रधानमंत्री ने रोहित के परिवार से संपर्क करने की जरूरत नहीं समझी। उनकी यह मांग है कि रोहित के साथ न्याय होना चाहिए।

दरअसल रोहित तो केवल एक उदाहरण है। हमारे जातिग्रस्त समाज में दलितों को नक्सल बताया जाना आम है। उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनके खिलाफ हिंसा की जाती है और भेदभाव भी। उदाहरणार्थ, सन् 2014 में सुधीर धावाले को 40 माह बाद नागपुर जेल से रिहा किया गया। उसे 60 अन्य आदिवासी व दलित कार्यकर्ताओं के साथ, गिरफ्तार किया गया था। वह सामाजिक असमानता पर प्रश्न उठाता था परंतु उस पर नक्सली होने के आरोप जड़ दिए गए। सुधीर की तरह देश में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें अपने हक मांगने के लिए राज्य के कोप का शिकार बनना पड़ता है।

जातिप्रथा केवल हिन्दू धर्म में है। इस व्यवस्था में किसी व्यक्ति का सामाजिक दर्जा और उसका पेशा उसके जन्म से निर्धारित होता है। कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, उसी में मरता है। नीची जातियों में जन्में व्यक्तियों के साथ अन्याय और भेदभाव होता है। किसी व्यक्ति की योग्यता या उसकी पसंद का कोई महत्व नहीं है। यही कारण है कि रोहित वैमूला ने सुसाईड नोट में अपने जन्म को ''प्राणघातक दुर्घटना'' बताया था। पुराने समय में दलित की परछाई भी अपवित्र समझी जाती थी। वे सभी अधिकारों से वंचित थे। आज भी दलितों द्वारा आवाज उठाए जाने या उनके सामाजिक उत्थान से वर्चस्ववादी शक्तियों को बहुत तकलीफ होती है और दलितों को किसी भी प्रकार से कुचलना, उनका लक्ष्य होता है। दलित दूल्हों को आज भी बारात में घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता और दलित महिला सरपंचों के साथ बलात्कार और उन्हें नंगा कर घुमाए जाने की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी छुआछूत की प्रथा है। दलित न तो मंदिरों में घुस सकते हैं और ना सार्वजनिक कुओं से पानी ले सकते हैं। परंतु अम्बेडकर द्वारा लाई गई जागृति, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और औपनिवेशिक काल में किए गए सुधारों के कारण भेदभाव और अछूत प्रथा आज उतने क्रूर और अमानवीय स्वरूप में विद्यमान नहीं है जैसे कि पहले थी। परंतु उसका केवल रूप बदला है, वह समाप्त नहीं हुई है। जिन लोगों को जाति प्रथा से लाभ होता है, वे इसे कभी समाप्त नहीं होने देंगे।

आरएसएस, दलितों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। इसका उद्देश्य समावेशी भारत का निर्माण या सामाजिक समानता स्थापित करना नहीं है। आरएसएस ने खैरलांजी की घटना का कभी विरोध नहीं किया। वह अंतर्जातीय विवाहों के खिलाफ है। दलितों से जुड़ने के पीछे आरएसएस के दो उद्देश्य हैं। पहला, दलितों की समानता व सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों को आत्मसात करना। आरएसएस, दलितों के संघर्ष को समाप्त करना चाहता है। दूसरा, मुसलमानों और ईसाईयों–जिन्हें आरएसएस बाहरी मानता है–से लड़ने के लिए आरएसएस दलितों का इस्तेमाल करना चाहता है। आरएसएस की स्थापना, स्वाधीनता के पूर्व ऊँची जातियों के पुरूषों ने की थी। इस संगठन ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं की। उसने हाशिए पर पड़े वर्गों के समानता और अपने अधिकार पाने के आंदोलन का हमेशा विरोध किया। आरएसएस, यथास्थितिवाद का हामी है जिसमें विशेषाधिकार प्राप्त जातियां और पुरूष समाज पर हावी बने रहेंगे। संघ का भारत हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम सैनानियों के सपनों के भारत से बहुत भिन्न है।

हिन्दुत्व की विचारधारा – जो आरएसएस के रग–रग में समाई हुई है–एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है, जिसमें पदक्रम और भेदभाव का बोलबाला हो। अगर आरएसएस को आज दलित मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ रहा है तो उसका कारण यह है कि डॉ. बी आर अम्बेडकर और अन्यों के अभियान के कारण, दलितों में उनके अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी है और वे सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। दलितों के मामले में संघ समरसता की बात करता है, समता की नहीं। वह चाहता है कि हर जाति की अलग–अलग पहचान बनी रहे और उच्च जातियों के विशेषाधिकार सुरक्षित रहें। उसे दलितों से तब तक समस्या नहीं है जब तक वे अधिकार और समानता नहीं मांगते। ऐसा क्यों है, इसे हम अम्बेडकर के इस निष्कर्ष से समझ सकते हैं कि जाति की असली जड़ें दरअसल धर्म – हिन्दू धर्म – में हैं। आरएसएस, हिन्दू धर्म और हिन्दुओं का प्रतिनिधि होने का दावा करता है। अतः अगर वह दलितों को सचमुच गले लगाएगा और समान दर्जा देगा तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि इस भेदभाव की जड़ में हिन्दू धर्म है। ऐसा करना आरएसएस के लिए आत्मघाती होगा और उसके अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगा देगा। क्या आरएसएस के समरसता के आंदोलन से दलितों की स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा?उत्तर है नहीं।

आरएसएस खुलकर जाति व्यवस्था का समर्थन करता आया है। यहां तक कि उसने यह दावा भी किया है कि जाति व्यवस्था, भारत के ''गौरवपूर्ण'' अतीत का भाग है। आरएसएस के सबसे बड़े चिंतक एम एस गोलवलकर ने अपनी पुस्तक ''बंच ऑफ थाट्स'' में बिना किसी लागलपेट के जाति व्यवस्था को औचित्यपूर्ण ठहराया है। ''ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं जिनसे यह जाहिर होता हो कि यह (जाति व्यवस्था) कभी भी हमारे सामाजिक विकास में बाधक बनी हो। वास्तविकता तो यह है कि जाति व्यवस्था ने हमारे समाज की एकता बनाए रखने में मदद की है'' (बंच ऑफ थाट्स, पृष्ठ 108)।

''इतिहास गवाह है कि मुसलमान, देश के उत्तर–पश्चिमी और उत्तर–पूर्वी हिस्सों पर आसानी से कब्जा कर सके क्योंकि वहां बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को तहसनहस कर दिया था। गांधार जो कि आज का कंधार है, का पूरी तरह से इस्लामीकरण कर दिया गया। इसके विपरीत, दिल्ली और उत्तरप्रदेश में मुस्लिम शासन के बावजूद हिन्दू धर्म शक्तिशाली बना रहा क्योंकि इन इलाकों में जाति व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाता था'' (बंच ऑफ थाट्स)।

भारत के दलित, और विशेषकर रोहित जैसे लोग अम्बेडकर के विचारों और उनके लेखन से प्रभावित हैं। जाति के उन्मूलन का आंदोलन चलाकर अम्बेडकर, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बन गए। उन्होंने दलितों से संगठित होने और शिक्षा प्राप्त करने का आव्हान किया। अम्बेडकर, समानता और प्रजातंत्र के पक्षधर थे। इस नायक को आरएसएस आत्मसात करना चाहता है और इसके लिए वह उनके चुनिंदा उद्धरणों का संदर्भ से हटाकर इस्तेमाल कर रहा है। संघ ने ठीक यही कई महान चिंतकों के साथ भी किया है। अम्बेडकर को यह अहसास था कि जब तक जातिप्रथा बनी रहेगी, भारत में असली व आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित नहीं हो सकेगा। मनुस्मृति, जो कि सड़ांध मारती जातिप्रथा की संहिता थी, में दलितों और महिलाओं के लिए भयावह सजाओं का प्रावधान है। डॉ. अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रति सार्वजनिक रूप से जलाई क्योंकि उनकी मान्यता थी कि यह पुस्तक दलितों के अमानवीकरण और उनके निचले दर्जे की प्रतीक है। यह दिलचस्प है कि आरएसएस के मुखपत्र 'आर्गनाईजर' ने अपने 30 नवंबर, 1949 के अंक के संपादकीय में इस बात पर खेद व्यक्त किया कि ''हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास की कोई चर्चा नहीं है। मनु के नियम बहुत प्राचीन हैं और आज भी पूरी दुनिया उन्हें प्रशंसा की दृष्टि से देखती है और उनका पालन करना चाहती है। परंतु हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए मानो मनुस्मृति का कोई महत्व ही नहीं है''।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आरएसएस, अम्बेडकर पर कब्जा करना चाहता है। संघ हमेशा से कहता आया है कि अम्बेडकर, देश के विभाजन के पक्ष में थे और द्विराष्ट्र सिंद्धात में विश्वास रखते थे क्योंकि वे मुसलमानों को विश्वसनीय नहीं मानते थे। भारतीय मुसलमानों पर अविश्वास करना तो दूर अम्बेडकर अपनी पुस्तक ''पाकिस्तान आर द पार्टिशन ऑफ इंडिया'' में लिखते हैं, ''हिन्दू समाज के कई निचले वर्गों की आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक आवश्यकताएं वही हैं जो अधिकांश मुसलमानों की हैं। और इसलिए, ये दलित, मुसलमानों के साथ कहीं अधिक आसानी से सांझा मोर्चा बना सकते हैं। उनके लिए ऊँची जातियों के हिन्दुओं से जुड़ना बहुत कठिन होगा क्योंकि ऊँची जातियों ने ही उन्हें सदियों से मानवाधिकारों से वंचित रखा है''।

यह विडंबना ही है कि 'आर्गनाईजर' ने हाल में अम्बेडकर पर केन्द्रित विशेषांक निकाला। सच तो यह है कि अम्बेडकर, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित जिस भारत के निर्माण के हामी थे, वह आरएसएस का भारत नहीं है। समानता पर आधारित भारत के निर्माण के लिए ही संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। क्या हम यह भूल सकते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के ठीक बाद, आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने रामजन्मभूमि आंदोलन शुरू किया जिसका लक्ष्य साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण था? आरएसएस समर्थकों ने मंडल आयोग के विरोध में रैलियां निकालीं और कई स्थानों पर संघ के उकसावे पर विद्यार्थियों ने आत्मदाह का प्रयास किया।

शिक्षा के मामले में आरएसएस, हमेशा से इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहता है। आरएसएस के इतिहास में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिनके विचार उसके एजेंडे से मेल नहीं खाते। यही कारण है कि गुजरात के स्कूली पाठयक्रम से दलित विद्वान पीए परमार लिखित पुस्तक ''राष्ट्रीय महापुरूष भारतरत्न डॉ. बी आर अम्बेडकर'' हटा ली गई। यह पुस्तक कक्षा छः से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए संदर्भग्रंथ के तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी। जैसे ही सरकार को यह ज्ञात हुआ कि इस पुस्तक में एक पन्ना जोड़ा गया है, जिसमें अम्बेडकर द्वारा ली गई उन 22 प्रतिज्ञाओं का विवरण है, जो उन्होंने हिन्दू धर्म त्यागते समय लीं थीं, इस पुस्तक को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। आरएसएस ने डॉ. अम्बेडकर द्वारा संसद में प्रस्तुत हिन्दू कोड बिल का कड़ा विरोध किया था। अकेले सन् 1949 में उसने दिल्ली में 79 सभाएं आयोजित कीं, जिनमें इस बिल को हिन्दू संस्कृति व परंपरा पर हमला बताते हुए नेहरू और अम्बेडकर के पुतले जलाए गए।

अगर कोई इस भ्रम में है कि समय के साथ संघ के विचार बदल गए हैं तो वह दिवास्वप्न देख रहा है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के मुखिया सुदर्शन राव द्वारा एक ब्लाग पर लिखे गए लेख ''इंडियन कास्ट सिस्टमरू ए रीएप्रेजल'' को पढ़कर कई लोगों को गहरा धक्का लगा। राव ने लिखा, ''प्राचीन काल में जाति व्यवस्था बहुत अच्छे से काम कर रही थी और किसी वर्ग ने कभी उसका विरोध नहीं किया। यह धारणा गलत है कि जाति व्यवस्था, सामाजिक शोषण की व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य निहित स्वार्थों के आर्थिक व सामाजिक दर्जे को सुरक्षित रखना था''। आरएसएस, भारत में जाति प्रथा के उदय के लिए मुसलमानों के हमले को दोषी ठहराता है। हाल में, आरएसएस ने कहा कि मुस्लिम राजाओं ने हिन्दुओं का मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें गौमांस खाने पर मजबूर किया और उनसे गायों को काटने और उनकी खाल उतारने का काम करवाना शुरू कर दिया। संघ का कहना है कि अछूत प्रथा इसी तरह अस्तित्व में आई।

सन् 2007 में नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि हाथ से मैला साफ करना एक ''आध्यात्मिक अनुभव'' है जिसके कारण दलित यह काम करते हैं। ऐसा लगता है कि अब उनके विचार बदल गए हैं और हाल में उन्होंने हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का अंत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भाजपा, संघ की विचारधारा में विश्वास रखती है और विशेषकर उत्तरप्रदेश व बिहार में, अधिक मत पाने के लिए दलितों को अपने झंडे तले लाना चाहती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दलितों को सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार दिए जाने की समर्थक है।

किसी भी समुदाय के विकास और उसे समान दर्जा दिलवाने के लिए राज्य को इस तरह के समुदायों के विकास के लिए समुचित संसाधनों का आवंटन करना चाहिए। अगर सरकार सचमुच दलितों की प्रगति में रूचि रखती है तो अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए पर्याप्त आर्थिक प्रावधान किए जाने चाहिए थे। सन् 2015–16 के बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए रूपए 30,850 करोड़ व आदिवासी उपयोजना के लिए रूपये 19,980 करोड़ आवंटित किए गए। सन् 2014–15 के बजट में इन दो मदों के लिए आवंटन क्रमशरू रूपये 43,208 करोड़ व रूपये 26,714 करोड़ था। जाहिर है कि बजट में इस कमी से दलितों और आदिवासियों को फायदा तो होने वाला नहीं है। यहां यह दिलचस्प है कि 2015–16 के बजट में कारपोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया।

आरएसएस और भाजपा, अपने हितों की रक्षा के लिए अम्बेडकर और दलितों का सम्मान करने का नाटक कर रहीं हैं। परंतु उन्हें न तो दलितों के अधिकारों से कोई मतलब है और ना ही उन रोहितों से, जो इस क्रूर प्रथा का शिकार बन रहे हैं। (मूल अंग्रेजी से अमरीश हरदेनिया द्वारा अनुदित)

"DELAYED GST IS BETTER THAN A FLAWED GST"

Is GST really going to make life of a tax payer easier??

OVES ALI KHAN

GST… GST... GST... Due to some political reasons, the most awaited TAX reform is still awaited but hopefully it will turn into a reality very soon as it is all set to be passed in the upper house of parliament in the on-going Budget session. The bill has already been passed in the lower house of parliament in the previous session as The Constitution (One Hundred and Twenty-second Amendment) Bill, 2014. After getting passed in upper house, it requires approval of 50% of state assemblies and then finally it will go for presidential assent.

GST is a revolutionary Tax reform which will change the structure of Indirect taxation and will change the accounting and trade practises in India, this is what we are listening from last 12-13 years.

As of now around 160 countries are following GST model of Indirect taxation, most of the countries are following unified GST model, whereas India is going to opt Dual GST model (like brazil and Canada), In dual GST both Centre Government and State Government levied tax on each type of transaction. Dual GST model which India is going to opt is a complex model with dual taxation system and multiple tax rates.

Now, Let us understand major concerns and issues of proposed GST Law:

TAX PAYER CONCERNS

MULTIPLE REGISTRATIONS: This concept is the biggest hurdle to Ease of Doing business, under current law an assessee having establishment at multiple locations in different states have to take multiple registrations for each state, to be governed by and controlled by respective State Revenue Authorities.

This mess of multiple registration and authorities will continue to exist in GST also.

MONTHLY RETURNS: Service provider may be required to file up to 5 monthly returnsunder each registration and an annual return as well (total 61 returns in a year). So, returns filling would not be less than a nightmare under GST. It will lead to lot of accounting, reconciliation and verification exercise, which in turn will increase compliance and administrative cost. It can be termed as a biggest "MOCKERY" to EASE OF DOING BUSINESS.

STOCK TRANSFER: This is really interesting; movement of goods even without consideration is subject to GST. Under current law it is not subject to tax on the basis that BUYER & SELLER CANNOT BE THE SAME PERSON.

1% ADDITIONAL TAX: GST is based on "DESTINATION PRINCIPLE" i.e. the state in which goods and services are consumed will get the revenue. In order to compensate origin state government has decided to levy 1% additional tax on Interstate transactions assigned to state of origin, with no credit to buyerexactly as per the present CST law. The situation is like government is still keen to keep past memories alive.

INPUT CREDIT: To avail Input credit output supplier needs check that Input supplier has made the payments else he needs to discharge from his own pocket. It will be available on the basis of actual data uploaded, so onus will be on tax payer to feed correct Information completely, timely and in an effective manner. Extra care along with regular reconciliation on real time basis is required, which in turn will increase the administrative cost of the tax payer.

HIGH GST RATES: Government is planning to keep GST rates very high, (around 20%-22%), This clearly means that under new law also nothing is there to tap informal sector, yet no fiscal planning has been done to widen the tax base by covering informal sector, only wild guesses are there about its size and contribution to overall trade. The situation is like Government wishes to recover loss of tax revenue from Informal sector by keeping its GST rates high and make formal sector pay for it.

IT INFRASTRUCTURE: After lot of research government has constituted a Goods and Service Tax Network (GSTN) to provide IT Infrastructure and Infosys limited has been shortlisted for the same. As I mentioned earlier returns load will be very high (61 returns per year) under GST, so it will be a big challenge. Our experiences with the websites of MCA and INCOME TAX is not at all good as they are unable to take the burden of last minutes rush, sometimes government was forced to extend the compliance dates due to last minutes failures of these sites. We can expect such issues with GST also as data involved here is exponentially high as compared to MCA or INCOME TAX.

INTER STATE TRANSACTIONS (IGST): For Interstate transactions IGST model of GST will replace CST under current law. Under GST each transaction of supply of goods and services will be charged with dual rate of taxes (i.e. both centre and state). Currently rate of CST is 2% and it will shoot to approx. 20% under GST, now you can better imagine what will be going to happen to the tax payer. In the present regime only centre is levying tax on such transactions.

SERVICE TAX RATES: Government is still working to set a standard GST rate to generate at least same amount of revenue which existing system is generating. But, in hurry they have raised service tax rates to 14.5% from 12.36% when service sector is struggling and it really needs a boost.

POLITICAL CONCERNS

COMPENSATION: Centre has promised states to compensate them for 5 years for any revenue loss due to GST. However, no modalities for determination and timelines for compensation has been discussed anywhere.

Important questions arising here is:

How centre will determine the loss of states on Incremental revenue collections basis or an average of last few years?

What will be the timeline for determination and compensation of such loss?

STATE GAINING EXTRAORDINARILY: No mention of the situation where state ends up gaining extraordinarily. Will the state transfer such excess revenue to the centre or it stays with such state govt.?

These are politically sensitive issues and unless duly addressed may lead to litigation and unwarranted confrontation between state and centre. And no one can understand the damage of tussle between Centre and State better than Delhiites

Only time will tell how big this reform is and how it will benefit the trade, Industry and consumers at large. As a matter of fact GST model which have single tax administration authority, have single standard tax rate or minimum rates, and kept minimum compliances are more successful than very complex Dual GST model.

As per my understanding any innovative method of revenue maximization or tax collection is termed as "MAJOR TAX REFORM" by our political parties or central and state government, it hardly matters to them whether things are getting easier and simpler for tax payer or not.

Some months ago, Finance Minister Arun Jaitley said the best was often the enemy of the good and that we should not look for the "ideal" GST in this first, hesitant effort. That is certainly true but it is equally true that the bad is also the enemy - and a mortal one - of the good. Which is what this bill is

As after waiting for the bill for more than 5 years for GST a few months delay will not hurt the business much.

Proposed Indian GST in its current form doesn't seem to offer much benefit/ relief to the trade, Industry and consumers at large. But our centre and state governments might get enriched with advanced and better mode of tax collection with high GST rates.

The writer is C.A. (an associate member of ICAI and founder member of think tank POLICY SAMVAD, who may be contacted at khan.uves@gmail.com, Web: www.khangargassociates.com.

– राम पुनियानी

रोहित वेमुला के संदर्भ में हिंदुत्व राजनीति और दलित प्रश्न

अपने–अपने राजनैतिक झुकाव के मुताबिक, रोहित वेमुला की मौत को कुछ लोग हत्या तो कुछ आत्महत्या बता रहे हैं। रोहित की मौत का मुख्य कारण उसका दलित होना, अंबेडकर स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन (एएसए) की गतिविधियों में उसकी भागीदारी और इस दलित समूह की राजनैतिक सक्रियता थी। दलितों से सीधे संबंधित मुद्दे उठाने के अलावा इस एसोसिएशन ने प्रजातांत्रिक अधिकारों से जुड़े कई अन्य मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए। इनमें बीफ भक्षण और मुंबई धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को दी गई मौत की सजा शामिल हैं। एसोसिएशन ने 'मुजफ्फरनगर बाकी है' फिल्म का प्रदर्शन भी आयोजित किया। यह फिल्म मुजफ्फरनगर हिंसा (2013) में सांप्रदायिक शक्तियों की भूमिका को बेनकाब करती है।

मई 2014 में मोदी सरकार के शासन में आने के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर अतिसक्रिय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) ने अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के अनुरूप, इन सभी मुद्दों पर एएसए का विरोध किया। शिक्षा के प्रांगणों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी प्रजातांत्रिक समाज में अपरिहार्य है। आरएसएस की विद्यार्थी शाखा एबीव्हीपी, एक दलित समूह द्वारा धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र से जुड़े मुद्दे उठाए जाने को पचा नहीं सकी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वेमुला की मौत का संबंध एएसए द्वारा उठाए गए मुद्दों से था। रोहित की इन मुद्दों पर क्या सोच थी यह उनके फेसबुक पेज से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ, हम देखें कि बीफ के मुद्दे पर उन्होंने क्या लिखा, ''बीफ खाना और बीफ समारोह आयोजित करना, उन लोगों के साथ अपनी एकता प्रदर्शन करने का प्रयास है जो बीफ से जुड़े कारणों से देश के विभिन्न स्थानों पर अपनी जानें गवां रहे हैं। अगर हम इस तथ्य को नहीं समझ पाएंगे कि भाजपा–आरएसएस–विहिप का बीफ–विरोधी अभियान, मूलतः, इस देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का उपकरण है तो हमें हमेशा यह पछतावा रहेगा कि हम हमारे देश में व्यापक जनाक्रोश के मूकदर्शक बने रहेंगे। गाय के आसपास बुना गया पूरा मिथक आज दलित–विरोधी कम और मुस्लिम–विरोधी अधिक है।''

इससे यह स्पष्ट है कि वेमुला केवल तथाकथित दलित मुद्दों तक सीमित नहीं थे वरन् उनकी सोच का कैनवास कहीं अधिक व्यापक था। समाज के हाशिए पर पड़े सभी वर्गों – दलित, आदिवासी, महिलाएं, श्रमिक व धार्मिक अल्पसंख्यक – से जुड़े मुद्दे आपस में गुंथे हुए हैं। वेमुला ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आज यदि बीफ भक्षण के मुद्दे पर भावनाएं भड़काईं जा रही हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भयाक्रांत करना है। यह इस तथ्य के बावजूद कि समाज के अन्य वर्गों के सदस्य भी बीफ खाते हैं। एक स्तर पर

मुजफ्फरनगर फिल्म का मुद्दा भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। गहराई से देखने पर यह समझना मुश्किल नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ वह सांप्रदायिक राजनीति के समाज को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत कर देश पर हिंदू राष्ट्रवाद लादने के एजेंडे का हिस्सा है। हिंदू राष्ट्रवाद, मानवाधिकारों का धुरविरोधी है। रोहित ने यदि याकूब मेमन को फांसी दिए जाने का विरोध किया तो यह उनके व्यक्तित्व के मानवीय पक्ष को दर्शाता है। वे मृत्युदंड के ही खिलाफ थे। पूरी दुनिया में मृत्यु दंड का विरोध हो रहा है, फिर चाहे यह दंड किसी भी प्रकार के अपराध के दोषी को दिया जा रहा हो। पूरी दुनिया में और भारत में भी मानवीय मूल्यों के हामी लोग मृत्यु दंड को समाप्त किए जाने के पक्ष में हैं। परंतु इसे आतंकवाद के समर्थन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

एएसए द्वारा धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक व मानवीय मुद्दों को उठाए जाने से एबीव्हीपी व एएसए में वैचारिक स्तर पर टकराव हुआ। एबीव्हीपी अध्यक्ष सुशील कुमार ने यह शिकायत की कि उनकी पिटाई की गई। इस आरोप की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई, जिसने आरोप को बेबुनियाद पाया। परंतु विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति के साथ हालात परिवर्तित होने लगे। केंद्रीय मंत्री बी दत्तात्रेय और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के दबाव में रोहित और उनके चार मित्रों को सजा दी गई। उनकी स्कालरशिप बंद कर दी गई और उन्हें होस्टल से निकाल दिया गया।

विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति को एक पत्र लिख कर यह अनुरोध किया कि दलित विद्यार्थियों को जहर और एक रस्सी दे दी जाए। परंतु पाषाण–हृदय, तानाशाह व दलित–विरोधी कुलपति ने जानबूझकर इस पत्र की अनदेखी की, जिसके नतीजे में यह त्रासदी हुई। रोहित की मृत्यु के बाद, सत्ताधारी दल ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे उसकी राजनीति पूरी तरह बेनकाब हो गई। दत्तात्रेय ने एबीव्हीपी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि एएसए ''जातिवादी, अतिवादी व राष्ट्रविरोधी राजनीति का अड्डा थी''। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने अपनी संकीर्ण सोच के अनुरूप यह कहा कि रोहित की मृत्यु का दलित मुद्दों से कोई लेनादेना नहीं है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि चूंकि रोहित की मां दलित और पिता ओबीसी थे, इसलिए रोहित को दलित कहा ही नहीं जा सकता। यह रोहित के साथ हुए घोर अन्याय को नजरअंदाज करने का प्रयास था–वह अन्याय, जिसके चलते रोहित ने अपनी जान ले ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रचारित किया जा रहा है जिसमें रोहित को आतंकवादियों का समर्थक बताया गया है।

टीवी बहसों में आरएसएस–भाजपा के प्रवक्ता ''राष्ट्रविरोधी व जातिवादी राजनीति'' पर बरस रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर जो कुछ कहा और वह कहने के लिए जो समय चुना उससे सब कुछ एकदम साफ हो गया। मोदी वैसे तो बहुत वाचाल हैं परंतु वे उन मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं जिनसे उनके हिंदुत्व के एजेंडे का पर्दाफाश होता हो। मोहम्मद अखलाक की पीट–पीटकर हत्या पर भी उन्होंने बहुत समय तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। रोहित के मामले में पांच दिन तक चुप्पी साधने के बाद उन्होंने एक छद्म–भावुक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि ''भारत मां ने अपना एक पुत्र खो दिया है''। परंतु उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों से यह नहीं पूछा कि वे ''भारत माता के इस पुत्र'' को राष्ट्रविरोधी क्यों बता रहे हैं। यह दलितों को प्रताड़ना और विश्वविद्यालय प्रशासन के दलित–विरोधी रूख पर पर्दा डालने का प्रयास थाय यह दत्तात्रेय, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और एबीव्हीपी की इस घटना में भूमिका को अनदेखा करने की कोशिश थी।

एक तरह से यह घटनाक्रम, हिंदुत्व की राजनीति की दुविधा को भी प्रदर्शित करता है। वह धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की विरोधी है और दलितों, अल्पसंख्यकों व प्रजातांत्रिक मूल्यों के पैरोकारों को आतंकित कर रही है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, संघ परिवार के सभी संगठनों को मानो पंख लग गए हैं। उन्हें अपने राजनैतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने का लायसेंस मिल गया है। भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास में अंबेडकर–पेरियार स्टडी सर्कल को प्रतिबंधित करने का असफल प्रयास किया था। अधिकांश विश्वविद्यालय परिसरों में सांप्रदायिक विद्यार्थियों के गुट आक्रामक हो गए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन हिंदुत्ववादी न भी हो तो ऊपर से दबाव लाकर उसे भाजपा का एजेंडा लागू करने पर मजबूर किया जा सकता है। सामाजिक न्याय के अभियानों का कड़ा विरोध किया जा रहा है। आरएसएस से जुड़ा सामाजिक समरसता मंच बहुत सक्रिय है। कहा जा रहा है कि संघ जाति में विश्वास नहीं करता और यह भी कि सभी जातियां बराबर हैं! इसका निहितार्थ यह है कि संघ परिवार जाति से जुड़े मुद्दों की अनदेखी कर जातिगत पदक्रम को बनाए रखना चाहता है। अगर हमें अपनी किसी बीमारी को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम बीमार हैं। अगर हम जाति से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज करेंगे या उन पर चुप्पी साधे रहेंगे तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जाना अवश्यंभावी है कि हम वर्तमान जाति समीकरणों को बनाए रखना चाहते हैं।प्रधानमंत्री ने अंबेडकर विश्वविद्यालय में अपने भाषण में अपनी आंखे भिगोने के पहले, विद्यार्थियों को यह सलाह दी कि उन्हें अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलना चाहिए, जिन्होंने बिना किसी शिकायत के अपमान और भेदभाव को बर्दाश्त किया। यही बात राजनाथ सिंह ने भी कही। हम सब को याद है कि इस सरकार द्वारा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त प्रो. वाय सुदर्शन राव ने जातिप्रथा का बचाव करते हुए कहा था कि किसी ने कभी उसके संबंध में शिकायत नहीं की। इस प्रकार, जहां एक ओर अंबेडकर को हिंदुत्व नायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिशें हो रही हैं वहीं हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक संगठन अलग–अलग तरीकों से जाति पदक्रम को संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)

'We Would Cry' If UK Leaves European Union: German Finance Minister

LONDON: German Finance Minister Wolfgang Schaeuble urged Britain today to stay in the European Union, warning that Europe could become less stable if it leaves and that the bloc could also become less competitive.

British Prime Minister David Cameron has called an in-out referendum on the country's EU membership on June 23.

Opinion polls suggest the result could be very close."If the UK would not be engaged (in) the European Union as a member, I think the UK would take the risk that continental Europe would be a little bit less stable, more volatile and that is not in Britain's interests," said Schaeuble, speaking in English. Schaeuble, addressing a conference organised by the British Chambers of Commerce in London, said Britain made a big contribution to the EU with its expertise in security and foreign policy.

British finance minister George Osborne, speaking at the same event, said it would be a mistake for Britain to leave the EU at a time of geopolitical instability and risks posed by developments in Russia, the Middle East and North Africa. Cameron and Osborne back Britain's continued EU membership but their ruling Conservative Party is deeply divided on the issue and several cabinet ministers support a "Brexit".

Schaeuble said Britain was a force for improving the competitiveness of the bloc, adding that he did not want to lose an ally in the fight to reduce unnecessary rules and regulations. Asked what he would do if Britain voted to leave the EU, Schaeuble joked: "We would cry."

-Agency

Israel prevents Belgian MPs from entering Gaza

The Israeli authorities have prevented six Belgiam MPs from entering the Gaza Strip to visit NGOs and see for themselves the dire humanitarian situation and suffering of the Palestinians, PalSawa.com reported on Wednesday.

The visit, which was scheduled on Tuesday, was pre-arranged with the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). In a statement, the MPs criticised the “illegal” Israel measure and said it contravened international conventions. They pointed out that they had been invited by the Palestine Legislative Council as representatives of different political parties in Belgium.

Myanmar Muslim activists trial postponed for new charges

YANGON: The trial of two Myanmar Muslims -- already given two years jail on immigration offenses -- was postponed until next week Thursday after they were told fresh charges were being levelled against them which could see them spend a total of five years in prison.

The 28-year-old man and 34-year-old woman are among three activists on trial from interfaith group Thint Myat Lo Thu Myar (Peace Seekers), which was founded by a Buddhist monk in 2013 after anti-Muslim riots broke out in Meiktila in central Myanmar.

Anadolu Agency

SUBSCRIPTION FORM
TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :.....
Address :.....
.....
.....
Email:.....
Contact Phone No.....
for donation ☐ /life ☐ /10 yrs ☐ /5 yrs ☐ subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-)
through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I,
Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
or email : **timesofpedia@gmail.com**

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch,
New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

Ending Someone's thirst is the Biggest Deed of Humanity

ADVERTISEMENT TARIFF
TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:

Language: English, Hindi and Urdu

Printing: Front and Back - 4 Colours , Inside pages - B&W

No. of Pages: 12 pages (more in future)

Price: Rs. 3/-

Print order: 25,000

Periodicity: Weekly

Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.

Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page

Please Add Rs. 10 for outstation cheques.

50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA
Send your subscriptions/memberships/donations etc.
(Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch , New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

समाचार पत्रों के आईने से

रोहित वेमुला की मां ने कहा, स्मृति ईरानी जी, यह सीरियल नहीं, रियल लाइफ है... तथ्य सामने लाइए

नई दिल्लीः हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला के परिजनों और मित्रों ने शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा। उन्हों ने दो टूक लहजे में कहा कि संसद में स्मृति ईरानी ने रोहित के खुदकुशी से जुड़े मामले में संसद में जो भी कहा गया, वह पूरी तरह से झूठ है।बता दें कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला ने पिछले महीने आत्महत्या कर ली थी और एक दलित छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर देशभर में खूब बवाल हुआ था।रोहित की मां राधिका वेमुला ने दिल्लीत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, स्मृति ईरानी जी, यह सीरियल नहीं है, रियल लाइफ है। तथ्ये सामने लाइए, उन्हेंम तोड़ने–मरोड़ने की कोशिश मत कीजिए।

गौरतलब है कि स्मृति ईरानी ने बुधवार को लोकसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए कहा था, इस बच्चेह और उसके शव को लेकर राजनीति की गई। किसी ने उसके पास डॉक्टर को नहीं जाने दिया। पुलिस ने कहा ...उस बच्चेी को बचान का एक भी प्रयास नहीं किया था। उसे डॉक्टतर के पास ले जाने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसके शव का सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पुलिस को अगले दिन सुबह 6.30 बजे तक उसके पास नहीं जाने दिया गया। मैं नहीं, तेलंगाना पुलिस यह कह रही है।श्रोहित के भाई राजा ने कहा, श्यह सब झूठ है। इसका उद्देश्य ऐसे मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना है जो बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।

वेमुला के परिवार और उनके दोस्तों द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेस की खास बातेंः

रोहित वेमुला सहित तीन छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था।

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस स्मृति ईरानी द्वारा संसद में बोले गए झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बुलाई गई। जिस दिन रोहित की मौत हुई, उस दिन किसी भी पुलिसकर्मी और डॉक्टर को उस कमरे में नहीं जाने दिया गया। रोहित को पुनर्जीवित करने की कोशिश नहीं की गई। जान–बूझकर यह झूठ फैला कर मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ने शाम सात बजे रोहित को मृत घोषित किया था। यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ने गुरुवार 25 फरवरी को सामने आकर इस बारे में बयान भी दिया था। उन्होंने बताया कि जब तक वह पहुंची, रोहित की मौत हो चुकी थी।

सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जिस कमरे में रोहित ने आत्महत्या की वहां एक तरफ मृत देह रखी हुई थी और पुलिस भी वहीं मौजूद थी।

कहा गया कि प्रोक्टोरियल बोर्ड की जांच में दलित वर्ग से भी लोग मौजूद थे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। निर्णय एग्जक्यूटिव काउंसिल में लिया गया, जहां कोई दलित प्रतिनिधि नहीं है।

27 नवंबर को हुई मीटिंग के मिनट्स रू वाइस चांसलर और चेयरमैन अप्पाराव को मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने नियुक्त किया। उन 11 सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं था।

पेज नंबर 4, निर्णय–5 रू इसमें साफ किया गया है कि मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर निर्णय लिया गया कि छात्रों को न तो हॉस्टल में रहने दिया जाएगा और न ही छात्र चुनाव में भाग ले सकते हैं।

स्मृति ईरानी सफेद झूठ बोल रही हैं। पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि वहां किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई थी।

रोहित की जाति के मामले में स्मृति और गहलोत ने एसीपी की रिपोर्ट को माना, जो किसी की जाति के बारे में जांच करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

रोहित की मां अनुसूचित जाति की हैं और रोहित की दादी, जिन्होंने उनकी मां को गोद लिया था वह भी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। जाति प्रमाण पत्र से साबित होता है कि वह दलित था।

पेज नंबर 4, निर्णय–5 रू इसमें साफ किया गया है कि मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर निर्णय लिया गया कि छात्रों को न तो हॉस्टल में रहने दिया जाएगा और न ही छात्र चुनाव में भाग ले सकते हैं।

ये सब झूठ स्मृति ईरानी ने सिर्फ इसलिए बोले हैं ताकि बीजेपी और उनके अधिकारियों की ओर से ध्यान भटकाया जा सके।

–एजेंसी

केंद्र सरकार के कारण 50 हजार करोड़ का घाटा,

वित्त मंत्री ने किया आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 विधान मंडल में पेश

पटना, 26 फरवरी 2016ः 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार करों के विभाज्य पुल में बिहार का हिस्सा 10.917 प्रतिशत से घटकर 9.665 प्रतिशत रह गया। इसका अर्थ यह हुआ कि 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान बिहार को लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये बातें सूबे के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुरूवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 पेश करने के बाद विधानसभा के एनेक्सी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही।

सूबे के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि वर्ष 2014–15 में अनाजों का उत्पादन 143.2 लाख टन था। जबकि 2010–11 में 103.52 लाख टन। इस वृद्धि का श्रेय 2014–15 में चावल के उत्पादन में हुई काफी वृद्धि को दिया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों में अनाजों का उत्पादन का स्तर 5.65 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। इससे राज्यवासियों की खाद्य सुरक्षा बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि पूंजीगत निवेशों में प्रचुर वृद्धि (8,954 करोड़ रुपए) के कारण बिहार का राज्यकोषीय घाटा 2010–11 के 3,970 करोड़ रुपए से बढ़कर 2014–15 में 11,178 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके बावजूद सकल राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से नीचे है।

श्री सिद्दीकी ने कहा कि हाल के दशक में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में निरंतरता रही है। वर्ष 2005–06 से 2014–15 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था 10.52 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकसित हुई जो देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच लगभग सर्वाधिक है। वर्ष 2012–13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के औसत का 37.0 प्रतिशत थी जो 2014–15 में बढ़कर 40.6 प्रतिशत हो गयी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2005–06 से 2014–15 के बीच कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 6.02 प्रतिशत रही है। यह विशेष महत्व की बात है क्योंकि राज्य की लगभग 90 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2005–06 से 2014–15 के बीच 15 प्रतिशत से अधिक विकास दर्ज करने वाले क्षेत्रों में संचार (25.58 प्रतिशत), निबंधित विनिर्माण (19.31 प्रतिशत), निर्माण (16.58), बैंकिंग एवं बीमा(17.70 प्रतिशत) और परिवहन/भंडारण/संचार (15. 08 प्रतिशत) शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014–15 में अनाजों का उत्पादन 143.2 लाख टन था। जबकि 2010–11 में 103. 52 लाख टन। इस वृद्धि का श्रेय 2014–15 में चावल के उत्पादन में हुई काफी वृद्धि को दिया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों में अनाजों का उत्पादन का स्तर 5. 65 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। इससे राज्यवासियों की खाद्य सुरक्षा बढ़ी है।

वहीं औद्योगिक विकास के मामले में श्री सिद्दीकी ने कहा कि वर्ष 2014–15 में औद्योगिक क्षेत्र का विकास 9.10 प्रतिशत की दर से हुआ जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर 9.44 प्रतिशत से थोड़ी कम है। वर्ष 2014–15 में औद्योगिक क्षेत्र की धीमी विकास दर का कारण विनिर्माण क्षेत्र का धीमा विकास है जिसकी दर 5 प्रतिशत से थोड़ी अधिक रही। यह वस्तुतरू पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की धीमी विकास दर की अभिव्यक्ति है।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से लेकर 2012–13 तक लगभग 30 प्रतिशत की सर्वोच्च कमी बरकरार रही। वर्ष 2013–14 और 2014–15 में यह कमी घटकर 20 प्रतिशत रह गयी। बिजली की औसत उपलब्धता ग्रमीण क्षेत्रों 6–8 घंटों से 14–16 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 10–12 घंटों से 20–22 घंटे हो जाने से राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2012–13 के 145 किलोवाट घंटा से बढ़कर 2014–15 में 203 किलोवाट घंटा हो गयी। यह दो वर्षों में लगभग 40 फीसदी की वृद्धि को दर्शाती है, जो देश में सर्वोच्च है। संवाददाता सम्मेलन में देश के जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ रॉकी राय, गोविन्द राव और स्थानीय एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट के सदस्य सचिव शैवाल गुप्ता भी उपस्थित रहे।

Smriti Irani schools opposition in Lok Sabha; impresses party principals

Smriti Irani schools opposition in Lok Sabha; impresses party principals

By the time Human Resource Development Minister Smriti Irani finished with her speech in Lok Sabha on Rohith Vemula's suicide and the JNU issue, she impressively justified her aggressive posturing throughout the day including her face off with Bahujan Samaj Party supremo Mayawati in Rajya Sabha.

In her response to over four-hour-long discussion, Smriti nonchalantly combined the role of a script-writer, producer, director, minister, actor, orator and a hurt woman into one -- all to perfection. Her speech was a mix of emotions, rhetoric, substance and melodrama (anger, loaded pause, tears rolling and occasional choking with emotions).

Thanks to her fiery delivery, the minister succeeded in convincing her political bosses and all in BJP's rank and file that she was competent enough to take on the high and mighty from the opposition ranks. This, at a time, when the entire opposition stood united against her, her government and the ideological stream she belonged to. Irani's speech on the floor of Lok Sabha was clearly an embodiment of the nationalist Hindutava thought process.

For those belonging to this school of thought, her speech would serve as a document helping them in the indoctrination process of generations that would choose this stream of ideology in future. The effect of her speech was such that Home Minister Rajnath Singh complimented her on floor of the House.

After today's speech in Parliament, Irani's detractors may have reasons to feel even more bitter about her but she did hike her importance both in the RSS-BJP hierarchy.

Irani appeared well-prepared to deliver a shock and awe counter strike on the Opposition benches as she was armed with loads of documents to supplement her claims. From official notes, books to radical left literature she was equipped with all weapons that were needed to prove her point. From the point go she made it apparent who was on her radar for offence -- Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Trinamool Congress and the Left.

It seemed she was waiting for this moment for quite some time -- to clear her name, her role as HRD minister, her government's position and to take on the opposition particularly the Congress and the Left. Anyone from the opposition benches who ever wrote to her seeking her's or her ministry's favour on different matters were at their wits end as Irani named everyone and asserted how effectively she addressed their issues.

Most of these requests were either related to admissions or appointments in different Central-

government aided institutions. Irani made it clear that she did not do any extra favour by sending repeated reminders to the Hyderabad Central University when her ministerial colleague Bandaru Dattatreya wrote multiple letters to her on different incidents happening in that university. She went on to quote letters written by Hanumantha Rao, Oommen Chandy, Shashi Tharoor (all Congress), Asaduddin Owasi, Pappu Yadav, Saugat Roy, Pradip Bhattacharya among others.

Hitting out at the Congress where it could hurt most, she targeted its vice president Rahul Gandhi by first talking about how Atal Bihari Vajpayee had called former prime minister Indira Gandhi "Durga" after 1971 war victory against Pakistan and the following liberation of Bangladesh.

"Chunao toh Indira Gandhi bhi hari thi lekin unke beton ne kabhi Bharat ki Barbadi ka nara lagane walon ka saath nahi diya (Indira Gandhi too had lost elections but her sons never supported those who shouted slogans for the destruction of India)," Irani said in an obvious reference to Rahul's father and former prime minister Rajiv Gandhi and his uncle Sanjay Gandhi.

Responding to the Congress's charge against her, Irani asked what her crime was. Was she being consistently targeted because she contested elections from Amethi (against Rahul Gandhi)? "Mera naam Smriti Irani hai meri jaat bata kar dikhao (My name is Smriti Irani, I challenge you to tell my caste). I am angry today because the mother who gives birth is accused of murder," said the minister in a voice that quivered with emotions.

She vehemently denied that she allowed Rohit Vemula's suicide to become a Dalit versus non-Dalit battle. Contrary to that she charged Rahul and other opposition leaders of playing politics over Rohit Vemula's dead body. "Have you ever seen Rahul Gandhi go to a place twice? Six hundred young boys died in the Telangana agitation. Did Rahul Gandhi visited even once? He went to Hyderabad twice. In his suicide note Rohit says nobody is responsible for his death. That report is from the Telangana Police, not mine," Irani said.

-Agency

United Muslims Front demands 18 percent Reservation for Muslims

United Muslims Front organized a press conference in Gomti Hotel at Lucknow UP demanding 18% Reservation for Muslims as was assured and promised by samajwadi Party in its poll manifesto of up elections 2012.

The conference was attended by Bhai tej singh National President of Ambedkar Samajwadi Party, Shamsher Pathan National President Awami Vikas Party, Dr VK Singh Yadav Pichda Samaj Party. Shahid Ali Adv, National President United Muslims Front has stressed upon d need of 18% Reservation for Muslims considering the plight of muslims and exhorted that if reservation is not accorded then they will not let samajwadi party to form govt in up next time.

Mr shamsher Pathan had also insisited to give reservation to muslims in terms of SP manifesto. Bhai tej Singh had stated that their Party is in full agreement with the demand of united muslims front.

मैडम मनु स्मृति अग्रवाल जी के नाम खुला पत्र

मैडम जी,

देश में लोकतंत्र है। एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनप्रतिनिधियों के लिए कोई शैक्षणिक अहर्ता निश्चित नहीं है। यह अनुचित भी नहीं है यदि कोई कम पढा जनप्रतिनिधि अपने लोकतांत्रिक अनुभवों से देश और समाज को सही दिशा दे। हमारे ही देश में भूतपूर्व राष्ट्रपति डा ज्ञानी जैल सिंह का उदाहरण हम सबके सामने है। लेकिन आप तो सबसे अलग हैं। अलग इसलिए कि आप एक अच्छी वक्ता हैं लेकिन अफसोस कि आप कुत्सित विचारों की स्वामिनी भी हैं।

लोकसभा में रोहित वेमुला और जेएनयू के मामले में सरकार की ओर से जवाब दिये जाने के क्रम में आपने अपनी कुत्सितता की सारी हदें पार कर दी। आपने रोहित वेमुला के संदर्भ में कहा कि – एक मरे हुए छात्र पर राजनीति की जा रही है। आपके राजनीतिक और सामाजिक चरित्र को देखते हुए आपके कहे पर आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। आपके लिए रोहित वेमुला बेशक मर गया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह देश के करोड़ों दलितों और पिछड़ों के दिलों में जिंदा है। उसके सजीव होने का ही परिणाम है कि आपको लोकसभा में किसी अदाकारा के जैसे लंबी स्क्रिप्ट पढनी पड़ी।

आपकी कुत्सित वैचारिकी का एक प्रमाण यह भी कि आपने अपने डायलाग में महिषासुर का देश के सबसे बड़े संवैधानिक मंच पर अपमान किया। जबकि देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग महिषासुर को अपना अराध्य मानते हैं। यकीन नहीं आये तो कभी मैसूर जाकर देखिए। महिषासुर की गगनचुम्बी प्रतिमा लगी है। कभी घुमने के लिहाज से ही उज्जैन जाइये आपको वहां भी महिषासुर का प्रमाण मिलेगा।

इतने से भी आपकी कुत्सितता ठीक नहीं होती है तो झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के सखुआपानी गांव जाइये। आपको वहां असुर जाति के लोग जिंदा मिल जायेंगे, जिनके लिए महिषासुर उनके पूर्वज हैं। झारखंड यदि दूर लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस चले जाइये। वहां गंगा के तट पर ही भैंसासुर (महिषासुर) का भव्य मंदिर है और सबसे सुंदर घाट भी। इतने से भी आपका दिल नहीं माने तो महोबा चले जाइए। वहां तो महिषासुर के मंदिर को भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने ही प्राचीनतम मंदिरों की श्रेणी में रखा है।

बहरहाल जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपकी लोकतांत्रिक समझ और योग्यता पर सवाल उठाना भारतीय लोकतंत्र का अपमान करना है, उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी बात को कहने से पहले उसके बारे में जानने–समझने का प्रयास करेंगी। वजह यह कि जानने–समझने की कोई उम्र नहीं होती है। वैसे भी भारतीय संसद आपके ष्सास भी कभी बहू थी३९ का शूटिंग स्पाट नहीं है। आपकी कुत्सित वैचारिकी पर अफसोस के साथ।

नवल किशोर कुमार

लालू–नीतीश की एकजुटता का गवाह बना राघोपुर

दोस्तों, मौका कच्ची दरगाह–विदुपुर पुल के कार्यारंभ समारोह का था। इस मौके पर कभी एक–दूसरे के घोर विरोधी रहे और अब महागठबंधन के दो सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मंच पर मौजूद थे। इन दोनों धुरंधरों के संबोधनों में खास बात यह रही कि दोनों ने लगभग एक ही सुर में मुख्य विपक्षी दल पर हमला बोला।

हालांकि हमला बोलने की शुरूआत उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने प्रारंभिक संबोधन में ही कर दी थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग लालू जी को कार्यक्रम में शामिल किये जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जबकि वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और महागठबंधन के बड़े नेता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने समारोह में सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था। लेकिन वे नहीं आये। श्री यादव ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष के लोग छाती पीटने का काम कर रहे हैं तो वे करते रहें, लेकिन हमारा काम सूबे का विकास करना है।

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। अपने चुटीले अंदाम में उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष खटमल की तरह है जिसका काम काटते रहना है। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार सहित सरकार में शामिल सभी मंत्रियों को सलाह भी दी कि वे विपक्ष के आरोपों को छोड़ अपना ध्यान बिहार के विकास पर केंद्रित करें।

जबकि इस पूरे समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे फार्म में नजर आये। उन्होंने न केवल लालू प्रसाद को महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता बताया बल्कि उन्हें लेकर विपक्ष द्वारा उठाये जा रहे सवालों का जवाब भी दिया। श्री कुमार ने कहा कि लालू जी कहीं भी जाते हैं तो विपक्षी नेता हंगामा मचाने लगते हैं। लेकिन लालू जी सूबे के सर्वमान्य नेता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू जी द्वारा किसी सरकारी पदाधिकारी को फोन किये जाने पर सवाल उठाना गलत है। सच्चाई है कि सभी दलों के जनप्रतिनिधि यही काम करते हैं। जब कोई आदमी किसी जनप्रतिनिधि के पास पहुंचता है तब हर जनप्रतिनिधि संबंधित पदाधिकारी को फोन करता है। यह सामान्य सी बात है। लेकिन लालू जी के मामले में विपक्षी दलों के नेताओं का बोलना बेमतलब का है।

बहरहाल पूरे समारोह में लालू–नीतीश दोनों ने अपने–अपने संबोधनों में महागठबंधन की एकजुटता को साबित करने का प्रयास किया। यहां तक कि राजद प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार द्वारा अबतक जितने भी कार्य किये गये हैं, उसमें घटक दलों की पूरी सहमति ली गयी है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि वे जानते हैं कि वे महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं ओर वे गठबंधन धर्म का सम्मान करना जानते हैं। इसके लिए विपक्षी दलों को अपना सिर खपाने की जरूरत नहीं है।

ٹائمس آف پیڈیا

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

TIMES OF PEDIA

NEW DELHI Page 12 Price ₹ 3.00

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इंसाफ़ की डगर पर

www.timesofpedia.com

WEEKLY HINDI ENGLISH URDU

WED 24 FEB - TUE 01 MAR 2016 VOL. 4 Issue 17 RNI No. DELMUL/2012/47011 P.Reg. No. DL(S) - 01/3431/2013 - 15

حسن روحانی کے دوبارہ صدر بننے کے امکانات روشن

ایران میں جمعے کو ہونے والے انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق صدر حسن روحانی سمیت اصلاح پسند رہنماؤں کو برتری حاصل ہے۔

حسن روحانی اور سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کو ایران کے رہبر اعلی کا انتخاب کرنے والی ماہرین کی اسمبلی میں برتری حاصل ہے۔

جبکہ پارلیمان میں ابتدائی نتائج کے مطابق لگ رہا ہے کہ اصلاح پسند تہران کی تمام 30 نشستیں جیت جائیں گے۔

عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری توانائی پر ہونے والے معاہدے کے بعد یہ ملک کے پہلے انتخابات ہیں گ

سامنے آنے والے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن روحانی سنہ 2017 میں دوبارہ ایران کے صدر منتخب ہو سکتے ہیں۔ ملک کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج نے حکومت کو مزید اعتبار اور اثر ورسوخ عطا کیا ہے۔

ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ 'اب مقابلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ایران کی اندرونی صلاحیتوں اور مواقع کے مطابق اقتصادی ترقی میں نیا باب شروع کرنے کا وقت ہے۔'

لوگوں نے ایک بار پھر اپنی طاقت ظاہر کی ہے اور اپنی منتخب حکومت کو مزید طاقت اور اعتبار دیا ہے۔' جمعے کو ووٹنگ کا وقت تین مرتبہ بڑھایا گیا۔ جبکہ ٹرن آوٹ 60 فیصد رہا۔

ان انتخابات میں ایرانی عوام نے دوہرے ووٹ کے ذریعے ملک کی پارلیمان کے ارکان کے علاوہ رہبرِ اعلیٰ کا انتخاب کرنے والے ماہرین کی اسمبلی 'مجلسِ رہبری' کے ارکان کا انتخاب کیا ہے۔ ان انتخابات میں تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ ایرانی ووٹ ڈالنے کے مجاز تھے۔

ایرانی پارلیمنٹ کی 290 نشستوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں 6200 امیدوار میدان میں تھے جن میں 586 خواتین بھی شامل ہیں تاہم 88 رکنی مجلسِ رہبری کے لیے کسی خاتون امیدوار نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ پارلیمانی انتخابات کے تحت 290 ارکان پارلیمان کو چار برس کے لیے منتخب کیا جائیگا جبکہ رائے دہندگان نے مجلسِ رہبری کے لیے 88 علما کا انتخاب کیا ہے جن کے رکنیت کی معیاد آٹھ برس کے لیے ہوتی ہے۔

خیال رہے کہ انتخابی مہم میں ملک کی معیشت ایک اہم موضوع رہا ہے۔

اصلاح پسند اور اعتدال پسندوں کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر توجہ دے رہے ہیں جس سے روزگار بڑھنے کے امکانات پیدا ہوں گے۔

لیکن قدامت پسند خیالات کے حامیوں کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی اندرونی طور پر پیداوار بڑھانے سے ہوگی۔

شام میں امریکی میزائل اور روسی ٹینک آمنے سامنے

امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے شام میں جاری جنگ کی ایک ویڈیوں پوسٹ کی ہے جس میں باغیوں کو امریکی ساخت کے میزائل کے ذریعے ایک روسی ساخت کے ٹینک کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھایا گیا ہے۔

اخبار کے مطابق سماجی رابطوں کی سائٹ پر شیئر کی گئی اس ویڈیو میں باغی پہلی بار امریکی ساخت کے اینٹی ٹینک میزائل سے روس کی جانب سے شامی افواج کو فراہم کیے گئے جدید 90T ٹینک کو نشانہ بنا رہے ہیں۔

حلب کے مضافات میں فلمائی گئی ویڈیو میں باغی جس میزائل کو فائر کر رہے ہیں اسے TOW71-BGM کہا جاتا ہے۔

واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اینٹی ٹینک میزائل سی آئی اے کی جانب سے شام میں لڑنے والے 'معتدل' باغیوں کو سنہ 2014 میں فراہم کیے گئے تھے۔

باغیوں کی جانب سے سماجی رابطوں کی سائٹس پر پوسٹ کی جانے والی متعدد ویڈیوز میں ان میزائلوں کے ذریعے سرکاری افواج کو نشانہ بناتے ہوے دیکھا جا سکتا ہے۔

امریکی اخبار کے مطابق جمعے کو پوسٹ کی جانے والی یہ ویڈیو اس لیے اہم ہے کیونکہ اس میں پہلی بار امریکی میزائل اور روسی ٹینک آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ روس گذشتہ برس سے شام کی حکومت کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور یہ جدید ٹینک بھی چند ماہ قبل ہی شامی افواج کو دیے گئے ہیں۔

ویڈیو میں میزائل ٹینک سے ٹکراتا ہے لیکن اس کے باوجود ٹینک تباہ نہیں ہوا اور ٹینک

کے عملے کو اس سے نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق یہ ٹینک ایک ایسے دفاعی نظام سے لیس ہے جو اپنے طرف آنے والے میزائلوں کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس وڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ نظام فیل ہو گیا تھا یا پھر اس وقت وہ بند تھا۔ 90T ٹینکوں کی باڈی پر میزائلوں سے بچنے کے لیے خصوصی آہنی زرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور شاید اسی زرہ نے ٹینک کو تباہ ہونے سے بچایا ہے۔

تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ مختلف جنگوں میں اپنے جدید ہتھیاروں کے کامیابی سے تجربے کرتا آیا ہے لیکن روس کو ایک لمبے عرصے بعد شام کے تنازعے کی شکل میں اپنے ہتھیاروں کو حقیقی میدانِ جنگ میں آزمانے کا موقع ملا ہے۔